साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 04-10 अक्टूबर 2021, वर्ष-7, अंक-27

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्रदेश के 75 फीसदी आईएएस कर रहे खेती-किसानी

अन्नदाता अफसर!

- प्रदेश में मप्र कैडर के अभी 359 आईएस अफसर
- मप्र के 215 अफसरों के पास खुद की कृषि भूमि
- किसानों की आय 2022 तक दो गुना करने का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका
- किसानों को उम्मीदः अब जरूर आएंगे अच्छे दिन, और खेती बनेगी लाभ का धंधा

अरविंद मिश्र। भोपाल

मध्य प्रदेश का हर तीसरा आईएएस अफसर किसान है। यह बात अलग है कि ज्यादातर आईएएस अधिकारियों के लिए खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकी है। हालांकि, कुछ अफसरों की खेती से आय होती है, लेकिन वह एक आम किसान को औसतन होने वाली आय से बहुत कम है। इन अफसरों द्वारा पेश वर्ष 2015-16 में संपत्ति के ऑनलाइन ब्योरे में यह खुलासा हुआ है। प्रदेश में अभी मप्र कैडर के 359 आईएएस अफसर हैं, जिनमें से 225 से ज्यादा ने अपने पास खेती की जमीन होना बताया है। इन अफसरों की राज्य के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने का रोडमैप तैयार करने में अहम भूमिका है। इससे मध्यप्रदेश के किसानों को भी उम्मीद है कि अगले साल तक उनकी आय दोगुना हो जाएगी। यही नहीं, उन्हें यह भी भरोसा है कि सरकार के साथ किसान अफसर जो तय करेंगे, उससे उनके अच्छे दिन आएंगे। किसानों के साथ ठगी और छलावा भी नहीं होगा। इधर, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर गंभीर हैं।

अफसरों को 'हुजूर' ज्यादा पसंद

भोपाल जिले के हुजूर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अफसरों के पास जमीनें है। राजधानी के बावड़िया कला, मेंडोरी, बिसनखेड़ी, बड़ियाकीमा, बरखेड़ी खुर्द, खुदागंज, छापरी, चौपड़ा कलां, रातीबड़, नीलबड़ से लेकर सीहोर तक आईएएस की जमीनें है। अफसरों ने केंद्र सरकार को जनवरी 2021 में अपनी संपत्ति (प्रापर्टी रिटर्न) की जो जानकारी भेजी है, उसमें कृषि और असिंचित भूमि का ब्यौरा है। दिलचस्प है कि ज्यादातर अफसरों ने मकान-फ्लैट के अलावा कृषि भूमि में निवेश किया है।

भोपाल में खरीदी जमीन

दरअसल, प्रदेश के आईएएस अफसरों को भोपाल में खेती-किसानी के लिए खेती की जमीन रास आ रही है। इसकी वजह है-यहां की आबोहवा। ये अफसर भले ही किसी अन्य प्रदेश के हों, लेकिन मप्र कैडर मिलते ही इन्होंने भोपाल के आसपास के गांवों में जमीनें खरीदीं। ये लोग गेहूं, चना से लेकर आधुनिक बागवानी और फल-फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे इन्हें कमाई भी हो रही है। इनमें से कई ने सरकार को अपनी इस कमाई के बारे में बताया है। प्रदेश में अभी मप्र कैडर के 359 आईएएस अफसर हैं। इनमें से 215 से ज्यादा (75 फीसदी) अफसरों के पास सिंचित और असिंचित जमीन है।

ये अफसर खेती से कमा भी रहे

एसीएस मोहम्मद सुलेमान के सहारनपुर में आम के बागान हैं। इससे सालाना 4.50 लाख की कमाई है। प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव अपनी जमीन से 1.10 लाख रुपए, अनुपम राजन को एक एकड़ कृषि भूमि से 60 हजार की कमाई होती है। अलका उपाध्याय को बाबई की जमीन से 1.60 लाख कमाई होती है। आईएएस एमके सिंह को भोपाल और रायसेन में 25 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर लगभग 9.5 लाख की आय होती है। पीएस संजय दुबे को भोपाल के बरई में 0.410 हेक्टेयर जमीन से सवा लाख रुपए की कमाई होती है। उमाकांत उमराव को रातीबढ़ में खेती से 20 हजार सालाना कृषि भूमि पर मिलते है।

इनके पास भी भोपाल में कृषि भूमि

मध्यप्रदेश कैडर के मनोज गोविल, केसी गुप्ता, वीएल कांताराव, अनिरुद्ध मुकर्जी, मनोहर अगनानी, एसके पॉल, संजीव झा, अनुराग जैन, राजीव रंजन, विनोद कुमार, शैलेन्द्र सिंह, राजेश चतुर्वेदी, बीआर नायडू, एसएन मिश्रा, एसबी सिंह, शिव नारायण रूपला, एमके चौधरी, अमित राठौर, उमाकांत उमराव, निकुंज श्रीवास्तव, शोभित जैन, एसएस कुमरे, अनुराग चौधरी, अल्का श्रीवास्तव, एमबी ओझा, अशोक भार्गव, राजेश बहुगुणा, जीवी रश्मि, संजीव सिंह, कृष्णा गोपाल तिवारी, एस सोमवंशी, प्रवीण सिंह, अनुराग वर्मा, बी कार्तिकेयन, आदित्य सिंह, हर्ष सिंह, ऋतुराज और एम मेघना के प्रापर्टी रिटर्न में कृषि भूमि दिखाई गई है। इनमें से कुछ अफसर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, जबकि कृषि जमीन भोपाल में है।

रीवा के प्रगतिशील किसान का फेंफड़े का अपोलो में चल रहा उपचार

विंध्य के बीमार किसान को देखने चेन्नई पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गौतम

अब तक इलाज में चार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हो चुकी खर्च

संवाददाता। भोपाल

रीवा जिले के प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह कोरोना की चपेट में आने के बाद पांच माह से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनका इलाज चेन्नई के अपोलो अस्पतला में चल रहा है। अभी तक उनके इलाज में चार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। परेशान परिजन राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। वहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम चेन्नई के अपोलो अस्पताल पहुंचे। जहां उपचाररत प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह से मिले। गौरतलब है कि किसान धर्मजय सिंह देवतलाब विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रकरी के निवासी हैं। अपोलो अस्पताल में किसान के बड़े भाई व परिवार के सभी सदस्यों से मिले। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी

दिया। इस दौरान जहां अपोलो अस्पताल प्रबंधन ने उनका स्वागत भी किया। वहीं विस अध्यक्ष ने धर्मजय के स्वस्थ्य होने की ईश्वर से कामना की। साथ ही आधा घंटे तक वहां चिकित्सकों से बात की और इलाज में डॉक्टरों का सेवा समर्पण देखकर उनका आभार भी माना। संभवत: मप्र में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र के किसान से मिलने इस तरह गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की इस पहल की राज्य सरकार के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी सराहना कर रहे हैं।

मई में हुए थे भर्ती

गत 30 अप्रैल को किसान को रीवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 2 मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जांच में पता चला था कि 95 प्रतिशत फेफड़ा संक्रमित हो गया है। 18 मई को चेन्नई तमिलनाडु के अपोलो (मेन) अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से अभी तक इलाज चल रहा है। हालांकि अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ्य हो जाएंगे।

केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में दी बड़ी सौगात

बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला जीआई-टैग

-खास किस्म दुनियाभर में बनेगी मप्र की पहचान

चिन्नौर की खासियत

- इस धान का चावल अधिक खुशबूदार होता है।
- यह धान की सभी किस्मों में सबसे उत्तम है।
- चिन्नौर 160 दिन में पकती है।
- हाइट- 150 सेमी
- किस्म-केवल चिन्नौर।
- उत्पादन-एक एकड़ में 7-8 क्विंटल।
- कीमत-90-100 रुपये प्रति किलो।

रफी अहमद अंसारी, भोपाल

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बालाघाट के चिन्नौर धान के चावल को जीआई टैग मिल गया है। केंद्र द्वारा बालाघाट के चिन्नौर चावल चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ट्वीट करके दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए आभार जताया है।

दरलअसल, दुनियाभर के बाजार में चिन्नौर की सुगंध से बालाघाट ही नहीं, बल्कि पूरा मध्य प्रदेश महकेगा। 2019 में कृषि विभाग बालाघाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद में जीआई-टैग (जियोग्राफिकल इंडीकेशन टैग) के लिए दावा किया था। महाराष्ट्र, ने भी जीआई-टैग के लिए अपना दावा पेश किया था। हालांकि परिषद ने मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौर को ही जीआई-टैग की अनुमति दे दी है।

फसल उत्पादन के क्षेत्र में विगत दो वर्षों में हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। जिसमें हमारी कृषि अनुसंधान टीम की भूमिका अहम है। अभी अभी मध्यप्रदेश के लिए बालाघाट जिले के चिनोर चावल को कृषि के क्षेत्र में पहला जीआई टैग मिला है यह हमारे लिए गौरव का विषय है। हम कृषि के क्षेत्र में और कई विशेष फसलों के लिए जीआई टैग लेने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे किसानों की उस फसल को विश्व स्तर पर नई पहचान मिले और अच्छे दाम मिल सकें।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह बोले- कृषि विभाग वृहद एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन पर कर रहा काम

अब क्लिक करते ही हाजिर होगी किसान की 'कुंडली'

कर्ज,फसल बीमा, सम्मान निधि में नहीं होगा घपला

विशेष संवाददाता। भोपाल

किसान को कम फसल बीमा मिलना, बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी और किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी सहित कई समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। देश का कृषि विभाग वृहद एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन पर काम कर रहा है, जो किसानों की रोजमर्रा की शिकायतों में अप्रत्याशित रूप से कमी ला देगा। यह दावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक खास बातचीत के दौरान किया है।

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि किसान की सारी भूमि, उस भूमि पर क्या फसल ले रहा है। साथ ही उस पर कितना कर्जा है। इसका सारा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। हर किसान को एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस यूनिक नंबर से एक क्लिक पर यह जाना जा सकता है कि किसान को किसान सम्मान निधि मिल भी रही है कि नहीं। किसान के फसल बीमा की क्या स्थिति है। उपरोक्त डेटाबेस का एक्सेस बैंकों को भी दिया जाएगा, जिससे वह तुरंत पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बना दे। अभी किसान को क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में एनओसी लेना जाना होता है बैंक उसकी भूमि की सर्च प्रक्रिया पृथक से कराती है।

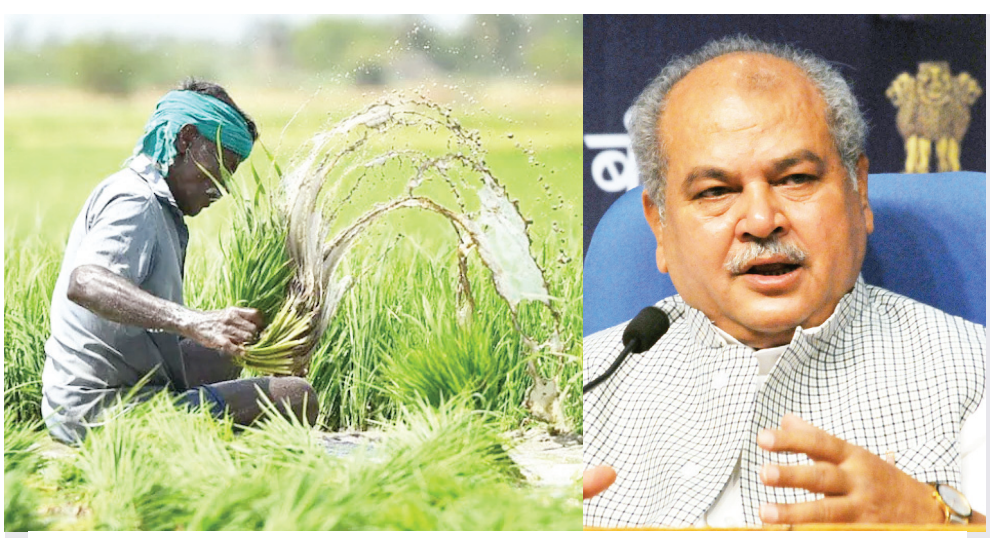

आठ करोड़ खाते लिंक करने का लक्ष्य

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कई नामी टेक कंपनियों से देश के विभिन्ना जिलों में इस डिजिटल मैपिंग मॉडल पर काम किया जा रहा है। जिस कंपनी का मॉडल सबसे बेहतर होगा उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उपरोक्त कंपनियों से एमओयू किया गया है, जो नि:शुल्क सेवाएं दे रही हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की भूमि से आधार कार्ड को लिंक करना इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अभी तक साढ़े पांच करोड़ खाते लिंक किए जा चुके हैं। इस साल इसे आठ करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

कुछ राज्यों के मन में बेइमानी

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों की स्थिति में सुधार किया है। लेकिन कुछ राज्य जानबूझकर उपरोक्त लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बेइमानी है। 21 करोड़ रुपए का प्रीमियम पीएम फसल योजना के तहत किसानों से मिला, जबकि 99 हजार करोड़ का भुगतान हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह योजना कितनी लाभप्रद है।

अपात्र किसानों से हो रही वसूली

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि यह सही है कि शुरुआत में जब पीएम सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी तब हड़बड़ी में राजस्व अमले ने गलत जानकारी दे दी थी जिससे अपात्रों के खाते में भी राशि पहुंच गई थी। लेकिन यह गलती पूरी तरह से सुधार ली गई है अब किसी भी अपात्र के खाते में राशि नहीं जा रही है। जिनके खाते में पहले पहुंच चुकी है उनसे वसूली की जा रही है।

-पांच फीट के पेड़ देने लगते हैं छह माह में फल

श्योपुर में उगाया ताइवान का पपीता

» आदिवासी महिलाओं की छह माह में आय हुई दोगुना

» अब और किसानों का इस ओर बढ़ रहा रुझान

संवाददाता। श्योपुर

मध्य प्रदेश के श्योपुर की करीब 50 आदिवासी महिला किसानों ने 50 एकड़ क्षेत्र में पपीता की ताइवान-786 किस्म के पौधे लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया है। इन किसानों की आय छह माह में ही दोगुना हो गई। इनके द्वारा इसी वर्ष मार्च-अप्रैल में लगाए गए पपीता के पौधे सितंबर आने तक चार-से पांच फीट तक की ऊंचाई के पेड़ बन गए हैं। इनमें से प्रत्येक पेड़ पर 50 किलो तक फल आ गए हैं। एक एकड़ में औसत उत्पादन 11 हजार 250 किलो है।

महिलाओं के इस प्रयास से उत्साहित होकर क्षेत्र के पांच हजार किसान अब पपीते की इस किस्म को उगाने की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासियों की रुचि परंपरागत खेती की जगह फलोद्यान के प्रति बढ़ाने के लिए मप्र आजीविका मिशन ने वर्ष 2019 में समूह से जुड़ी महिलाओं को जयपुर, जबलपुर, भोपाल सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण करवाया और इन्हें पपीता के बाग लगाने के लिए जागरूक किया। इस वर्ष मार्च-अप्रैल में दुबड़ी, बरगवां, बमोरी, कानखेड़ा, चितारा, डूडीखेड़ा, सैमरा, आमेठ, रानीपुरा, करियादेह आदि गांवों में प्रति किसान एक-एक एकड़ में ताइवान-786 पपीता के बगीचे तैयार किए। आजीविका मिशन ने 12.50 रुपए प्रति पौधा की दर से महिला किसानों को पौधे मुहैया कराए। एक एकड़ में करीब 250 पौधे लगाए गए।

श्योपुर की दोमट मिट्टी पपीता के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए यह ताइवान 786 सहित अन्य वैरायटी के लिए लाभप्रद है। कई गांवों में किसानों ने ताइवान पपीते के बगीचे तैयार किए हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी होगी।

डॉ. लाखन सिंह गुर्जर, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, श्योपुर

पपीते से आय हो गई एक लाख

दुबड़ी गांव की काली बाई अपने बगीचे में फलों से लदे पपीते के पेड़ को दिखाते हुए बताती हैं कि हमने एक एकड़ में पपीते का बाग लगाया था। पेड़ फलों से लद गए हैं। पपीते के लिए मिशन ने हमें जमीन और पौधे उपलब्ध कराए। एक एकड़ में एक लाख रुपए से अधिक कीमत के पपीते हो गए हैं। कम लागत में इस बार दोगुना से अधिक लाभ हुआ है।

आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पपीता के बाग तैयार कराए थे। अब हम एक जिला-एक उत्पाद में अमरूद के साथ पपीता के बाग लगाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। किसानों की भी रुचि बढ़ रही है।

राजेश शुक्ल, सीईओ, जिपं श्योपुर

6वीं तक के बच्चों को 10, इसके ऊपर वालों को 15 किलो फ्री मिलेगी

सरप्लस खरीदी गई 600 करोड़ की मूंग मिड-डे मील में बच्चों को बंटेगी

संवाददाता। भोपाल

मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील के तहत अब खड़ी मूंग बांटी जाएगी। ये वह मूंग है, जिसकी मप्र में सरप्लस खरीदी की गई है। इसे केंद्र सरकार नहीं उठी रही। लिहाजा स्कूलों के 68 लाख बच्चों को 85 हजार टन मूंग वितरित की जाएगी। पहली से छठवीं तक के बच्चों को 10 किलो और इससे ऊपर की कक्षा वाले छात्र-छात्राओं को 15 किलो मूंग मुफ्त मिलेगी।

राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 7196 रुपए में मूंग खरीदी है। लिहाजा 85 हजार टन मूंग की कीमत करीब 611 करोड़ रुपए पड़ेगी। पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मंत्रियों की ओर से सैद्धांतिक सहमति हो गई है। वित्त विभाग की सहमति मिलते ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस साल मार्कफेड ने 4.40 लाख टन मूंग खरीदी है, जिसमें से 2.50 लाख टन कोटे के तहत है। शेष सरप्लस है।

खर्च की राशि से निकलेगा मूंग का पैसा

अधिकारियों ने रास्ता निकाला है कि स्कूलों बच्चों को जितनी भी मूंग मुफ्त बंटेगी, उसका पैसा मिड-डे-मील के ही एक फंड से समायोजित किया जा सकता है। खाना बनाने पर प्रतिदिन प्रति बच्चा एक रुपए खर्च होता है। सालाना यह खर्च 674 करोड़ बैठता है। इसी पैसे को मूंग की खरीदी में डाल दिया जाएगा। यानी बच्चों को मुफ्त मूंग देने के बाद भी सरकार को कोई नुकसान नहीं है। खाना बनाने वाली राशि बची हुई है, क्योंकि कोरोना में बच्चे स्कूल नहीं गए और खाना नहीं बना। मिड-डे मील में पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाता है।

संचालकों को मांगना पड़ रही भीख, अब बिगड़ने लगी स्थिति

प्रदेश की 627 गौशालाओं में एक साल से नहीं मिला अनुदान

ग्वालियर। प्रदेश में गोशालाओं को 11 माह से अनुदान नहीं मिला है। जिससे गौशालाओं में स्थिति बिगड़ने लगी है। अब हालत यह हो गए हैं कि गौशाला संचालकों को गौशाला चलाने के लिए भीख मांगना पड़ रही है। बारिश में भूसा और चारा महंगा होने से परेशानी बढ़ गई है। ग्वालियर में भी गौशालाओं को 11 माह से अनुदान नहीं मिला है। कांग्रेस शासन में गाय के भूसे व चारा के लिए 2 रुपए से राशि बढ़ाकर 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से कर दी गई थी। कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की 627 गौशालाओं के अंदर रहने वाली एक लाख 66 हजार 804 गौवंश के लिए तीन-तीन माह की किश्त के रूप में पैसे दिए जाते थे। इसके बाद सरकार बदलने के बाद अक्टूबर 2021 से गौशालाओं को पैसा मिलना बंद हो गया। मप्र में 627 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, इनमें 1 लाख 66 हजार 804 गौवंश रहता है। यह गौशालाएं समाज और संस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती हैं।

एक गाय को 20 रुपए मिलते थे

कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 627 गोशालाओं में अनुदान बंद होने से 1 लाख 66 हजार 804 गौवंश भगवान भरोसे हैं। संस्थाओं को दानदाताओं से दान लेकर अथवा अन्य प्रयास कर पैसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

किसानों के लिए खुशखबरी: देश को मिली 35 नई फसलों की वैरायटी

नई फसलों की वैरायटी से कुपोषण मुक्त होगा भारत

» पीएम मोदी बोले- कृषि विज्ञान के तालमेल से बढ़ेगी किसानों की आय
» किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने बैंकिंग सिस्टम हुआ और आसान

संवाददाता। भोपाल/नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी। हाल ही में पीएम ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए फसलों की वैरायटी में मुख्य रूप से मुरझाई और बंध्यता मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में, गेहूं की जैव-फोर्टिफाइड किस्में, बाजरा, मक्का और चना, क्विनोआ, पंखों वाला बीन और फैबा शामिल है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की हैं। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है।

किसानों की बढ़ेगी आय

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया गया है। देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को 35 नई फसलों की वैरायटी को समर्पित किया गया है। इस कदम से किसानों की आय अवश्य बढ़ेगी।

पोषण युक्त बीजों पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नॉलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में, नई परिस्थितियों के अनुकूल, अधिक पोषण युक्त बीजों पर हमारा फोकस बहुत अधिक है।

कृषि संबंधी कहावतें लोकप्रिय

हमारे यहां उत्तर भारत में घाघ और बटुरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। घाघ ने आज से कई शताब्दि पहले कहा था-जेते गहिरा जोतै खेत, परे बीज फल तेतै देत। यानि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है।

11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए

पीएम ने कहा कि खेती-किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें अलग-अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं।

खरीद प्रक्रिया में सुधार

पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक-से-अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। इसके लिए किसानों को 85 हजार से अधिक का भुगतान किया गया है।

ग्रीन कैंपस अवार्ड्स का लक्ष्य

ग्रीन कैंपस अवार्ड्स का उल्लेख करते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को ऐसी प्रथाओं को विकसित करने या अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है जो उनके परिसरों को और अधिक हरा-भरा और स्वच्छ बनाएगा, और छात्रों को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

कम पानी वाली गेहूं कि किस्म लाएगी अच्छे दिन

इधर, रातलाम जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र जावरा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जलवायु सहिष्णु कृषि पद्धति एवं तकनीकियों का व्यापक अभियान समारोह का संजीव प्रसारण किया गया। जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित विशेष गुणों वाली 35 नई फसल किस्मों को भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया। कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैम्पस अवॉर्ड वितरित किए। वहीं समाराह के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में अधिकांश किसान छोटी जोत वाले हैं, जिनके जीवन में सकारात्म बदलाव लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। जिससे वे देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान कर सकें। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. डीआर पचौरी ने किया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख डॉ. सर्वेश त्रिपाठी ने पीपीटी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट एवं बीमारियां के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजातियों के विषय में किसानों को अवगत कराया। डॉ. सीआर कांटवा द्वारा किसानों को कम पानी वाली गेहूं की किस्मों के विषय में जानकारी दी। डॉ. रामधन घसवा ने कृषकों को कृषि उपयोगी विभिन्न मोबाइल एप्स के विषय पर जानकारी दी। डॉ. बरखा शर्मा द्वारा पोषण सुरक्षा में मिलेट्स एवं पोषण गृह वाटिका के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान की। डॉ. रोहताष सिंह भदौरिया ने रबी उद्यानिकी फसलों के विषय में जानकारी दी। डॉ. सुशील कुमार ने पशुपालन से संबंधित जानकारी दी। डॉ. जीपी तिवारी ने जलवायु परिवर्तन और डॉ. शिश राम जाखड़ ने मृदा स्वास्थ्य के बारें में किसानो को जागरूक किया गया। इस दौरान एक सैकड़ा के करीब कृषक/महिला किसानों सहित अधिकारी मौजूद थे।

पीएस ने टटोली भोपाल संभाग के उपार्जन और पीडीएस कार्यों की नब्ज, अफसरों ने कहा

अब किसानों से लाल धान नहीं खरीदेगी सरकार

» अब हर जिले में क्वालिटी कंट्रोलर अस्थाई तौर पर नियुक्ति किए जाएंगे
» जिस खाते से आधार नंबर होगा लिंक, उसी में होगा किसानों का भुगतान

विशेष संवाददाता। भोपाल

जिन किसानों का खाता आधार से लिंक होगा, सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में सरकार धान खरीदी का भुगतान करेगी। इतना ही नहीं, रबी सीजन की फसल के समय गेहूं खरीदी का भी भुगतान आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। यह निर्देश प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने दिए हैं। दरअसल, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में भोपाल संभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान मिलिंग एवं उपार्जन की समीक्षा बैठक संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी सहकारी बैंक के प्रबंधक और खरीदी केंद्र के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के खाते में आधार लिंक नहीं है, उन्हें तत्काल सूचना भेजकर आधार लिंक करा लें। सभी पंजीकृत किसानों के खाते से आधार लिंक होना जरूरी है। भोपाल में 25 किसानों का पंजीयन धान खरीदी के लिए हुआ है। वहीं सीहोर और रायसेन में पांच हजार मीट्रिक टन का खरीब फसलों का रकबा है। ऐसे में सभी किसानों के लिए कोआपरेटिव बैंक के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यवस्था बनाएं।

उपार्जन केंद्रों में जल्द बनवा लें प्लेटफार्म

प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि वेयर हाउस में समान रूप से गेहूं वितरित किया जाए। ऐसा न हो कि कुछ वेयर हाउस पूरे भरे हैं, तो कुछ पूरी तरह से खाली हैं। प्रमुख सचिव ने तो यहां तक कहा कि जिन मंडी और उपार्जन केंद्रों में प्लेटफार्म बनाना प्रस्तावित है, वह काम अनिवार्य रूप से करा लें। वहीं सभी धान की मिलिंग कराकर पीडीस दुकानों में चावल की सप्लाई कर दी जाए।

सिर्फ खरीदेंगे अच्छा अनाज

बैठक में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सवाल किया कि कुछ शिकायतें आती हैं कि लाल धान है। इसे खरीदा जाना चाहिए या नही। इस पर प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति तरुण पिथोड़े ने स्पष्ट किया कि लाल धान के नाम पर कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता है। मिलिंग के दौरान भी अगर लाल धान है तो यह नहीं खरीदना चाहिए। हम अच्छा अनाज खरीदेंगे, तभी तो लोगों को अच्छा अनाज वितरित कर सकेंगे। 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी धान में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर जिले में क्वालिटी कंट्रोलर अस्थाई तौर पर नियुक्ति किए जा सकते हैं। जो इसकी निगरानी करेंगे।

यह रहे मौजूद

बैठक में आयुक्त सह पंजीयक सहकारिता, प्रबंध संचालक, मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, आयुक्त सह प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स बैंक, भोपाल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, भारतीय खाद्य निगम नियंत्रक नापतौल भोपाल सहित संभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

जीवन-यात्रा को पर्यटन से जोड़ रहा मप्र

लेखक- प्रदेश की पर्यटन संस्कृति और आध्यात्म मंत्री हैं

जीवन के विविध आयामों से गुजरती जीवन-यात्रा मानव के चित्त को परमात्मा से जोड़ती है। लोक से परलोक, भौतिकता से आध्यात्म, अंधकार से प्रकाश और आत्मा से परमात्मा तक के सफर को समेटे हुए मानव अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जीवन-यात्रा के इन विविध पड़ाव और आयामों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन से जोड़ने की अभिनव पहल की है। इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश के पर्यटन विभाग ने अंतर-विभागीय और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

पर्यटन विभाग ने मानव की जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ाव और आयामों को धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और स्वास्थ्य के साथ जोड़कर विकसित किया है। इससे आरामदायक और सुलभ पर्यटन के साथ मनुष्य का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन संभव हो सकेगा। मनुष्य की बाल्य-काल से वृद्धावस्था तक के सफर में उसकी रुचियों और आवश्यकता में निरंतर परिवर्तन होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने बच्चों के लिए साइकिलिंग, पतंगबाजी और इंडोर गेम्स जैसी रोचक गतिविधियां, युवाओं के लिए पैराग्लाइडिंग, बैलून सफारी जैसी साहसिक गतिविधियों के साथ वृद्धजन के लिए वैलनेस और आयुर्वेदिक पंचकर्म जैसी सुविधाएं पर्यटन स्थल पर उपलब्ध करायी गई हैं। इस तरह हर आयु वर्ग के लिए पर्यटन स्थल पर पर्याप्त रोचक, साहसिक और मनोरंजक गतिविधियां संचालित करने के नवाचारों और नीतिगत परिवर्तनों के फल स्वरूप विश्व के प्रतिष्ठित ट्रेवल पब्लिकेशन लोनली प्लैनेट ने मप्र पर्यटन को वर्ष 2020 में बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन में तृतीय स्थान पर रखा है। व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञानवर्धन के साथ धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन भी आवश्यक होता है। पर्यटन विभाग ने संस्कृति और आध्यात्म विभाग के परस्पर समन्वय से व्यक्तित्व विकास के लिए पर्यटन के विभिन्न आयाम को शामिल किया है। इनमें अनुभूति पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, मॉनसून पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वैलनेस टूरिज्म और रॉक आर्ट टूरिज्म जैसे नवाचार पर्यटकों को रोचक जानकारी और अनुभव देने के साथ उनके व्यक्तित्व विकास में योगदान देंगे। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समीप अन्य अहम पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। इन सर्किटों में पर्यटको को पर्यटन के साथ आसपास के क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत, म्यूजियम और स्थानीय संस्कृति से परिचित मिलेगा। वहीं स्थानीय निवासियों को आर्थिक उन्नयन के साधन उपलब्ध होंगे। यह दोनों के लिए ही विन-विन सिचुएशन होगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 1500 से अधिक होमस्टे विकसित किए जाएंगे। पर्यटक को पर्यटन स्थल के समीप ही स्थानीय संस्कृति से परिचय, स्थानीय व्यंजन के स्वाद, हस्त-कला और हस्त-शिल्प के उत्पादों को क्रय करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड मे बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी में नामांकित किया गया है। अगले 5 वर्ष में प्रदेश के 100 गांवों को ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इनमें ओरछा, खजुराहो, मांडू, सांची, पचमढ़ी, तामिया, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, पेंच और कान्हा नेशनल पार्क आदि क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का चयन कर विकास किया जाएगा। प्रदेश के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अनायास ही पर्यटक आकर्षित हो जाते है। मॉनसून पर्यटन वर्षा काल में पर्यटकों को प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय कराने के लिए जंगल में बफर में सफर कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन में पर्यटकों ने जंगल के बफर जोन में सफारी का आनंद लिया। साथ ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बैलून सफारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे। पर्यटकों ने बताया हॉट एयर बैलून में ऊंचाई से राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली और सुंदरता को निहारना उनके जीवन का न भूलने वाला पल बन गया है। प्रदेश के नागरिकों को पर्यटन के दौरान ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुभूति पर्यटन के लिए पन्ना में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद द्वारा कार्य-योजना बनाई गई है। यहां पर राज्य का आर्ट डायमंड म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। पन्ना प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से हीरे प्राप्त होते हैं। पर्यटकों को हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां म्यूजियम में उपलब्ध कराई जाएगी। कैंपिंग और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साहसिक पर्यटन अंतर्गत प्रदेश में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर साइकिल टूर, वॉटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग, हॉट एयर बैलून सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही मांडू उत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह और जल महोत्सव में युवाओं के लिए म्यूजिक कंसर्ट का भी आयोजन किया जा रहा हैं। प्रदेश के धार्मिक स्थल और वहां की आध्यात्मिक अनुभूति अपने आप में विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह धार्मिक स्थल परमात्मा से संपर्क का सीधा माध्यम है। पर्यटकों को धार्मिक स्थलों तक पहुँच सुगम और कुशल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन अंतर्गत प्राचीन नगरी उज्जैन, चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर, महेश्वर, मंदसौर, ओंकारेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा आदि में सुलभ और आरामदायक पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया है। अब पर्यटक इन स्थलों पर धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति के साथ आस-पास के स्थलों पर मनोरंजन और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। अधिक उम्र और वृद्ध पर्यटकों के स्वास्थ्य की चिंता भी पर्यटन विभाग को है। वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वैलनेस सेंटर पर पर्यटक के लिए योग, आयुर्वेद पद्धति से पंचकर्म, कायचिकित्सा, मेन्टल हेल्थ व्यायाम जैसी चिकित्सा और वैलनेस सुविधाएं उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग की इकाइयों जैसे होटल होलीडे होम्स अमरकंटक, सैलानी आईलैंड रिजॉर्ट सैलानी, गांधी सागर डैम के समीप स्थित हिंगलाज रिजॉर्ट मंदसौर, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़, किपलिंग कोर्ट और इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ओरछा आदि प्रमुख शहर में वैलनेस सेंटर स्थापित किए जायेंगे। महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश की प्राथमिकता है।

आंदोलनककारी किसान उड़ा रहे धज्जियां

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को बाधित करने वाले किसान संगठनों को जिस तरह आड़े हाथ लिया, उससे यह उम्मीद बंधती है कि लोगों को अराजकता से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जब तक ऐसा हो न जाए, तब तक संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि किसान संगठनों की ओर से दिल्ली के सीमांत इलाकों में सड़कों को बाधित किए हुए दस माह बीत चुके हैं। इसके अलावा वे पंजाब एवं हरियाणा में टोल प्लाजा पर कब्जा किए हुए हैं और कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर धरना देकर उनका कामकाज भी प्रभावित कर रहे हैं। यह आंदोलन के नाम पर की जाने वाली खुली अराजकता ही नहीं, कानून के शासन की अवहेलना भी है। यदि ऐसे अलोकतांत्रिक और अराजक तौर-तरीकों को सहन किया जाएगा तो फिर इससे लोकतंत्र का उपहास ही उड़ेगा। नि:संदेह यह स्थिति इसीलिए बनी, क्योंकि पुलिस और सरकारों के साथ अदालतों ने भी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी का सही तरह पालन नहीं किया। यह क्षोभ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार यह कहे जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं कि धरने-प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया कि उसके आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? सड़कों पर कब्जे तो लोगों को बंधक बनाने वाली हरकत है। इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह सवाल पूछा कि आखिर राजमार्गों को बाधित कैसे किया जा सकता है और फिर दिल्ली के अंदरूनी हिस्से में धरना देने को आतुर किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने पहले ही शहर का गला घोंट रखा है। इस फटकार के साथ उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों से अवैध कब्जे हटें। आखिर सुप्रीम कोर्ट सरकारों को इन कब्जों को हटाने के आदेश क्यों नहीं दे पा रहा है? सवाल यह भी है कि वह कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए गठित समिति की रपट पर गौर क्यों नहीं कर रहा है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है, क्योंकि यह समिति खुद उसी ने गठित की थी। इतना ही नहीं, यह समिति गठित करते हुए उसने कृषि कानूनों के अमल पर रोक भी लगा दी थी। एक तरह से किसान संगठन उन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। उनकी जिद है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन यदि संसद से पारित कानूनों को किसी के सड़कों पर बैठ जाने से वापस लिया जाने लगा तो फिर किसी कानून की खैर नहीं।

प्राकृतिक कृषिः स्वस्थ किसान, रोगमुक्त फसल और अच्छा भाव

सम्पूर्ण देश में डॉ. सुभाष पालेकर द्वारा विकसित प्राकृतिक कृषि विधि से गन्ने की खेती की जा रही है और उसके अनेक लाभ सामने आए हैं। जिन्हें जानना व समझना आवश्यक है। पिछले वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक खेत बारिश से बाढ़ में 10 से 15 दिन तक पानी में डूबे रहे। परिणामतः रासायनिक खेत के गन्ने की फसल सूख गई, परन्तु गौ आधारित पालेकर विधि से किए गए गन्ने के खेत सुरक्षित रहे और पूरा उत्पादन मिला।

मुजफ्फरनगर, थाना भवन के गौ आधारित प्राकृतिक किसान धर्मपाल सिंह पिछले 10 वर्ष से पालेकर विधि से ही गन्ने की खेती कर रहे हैं। उनके अनुसार इस विधि से पानी की बहुत बचत होती है, जिसके कारण भूजल दोहन कम होता है और वर्षाजल सोखने की क्षमता भूमि में बढ़ने से भू-जल स्तर बहुत अच्छा हो गया है। जो ट्यूबवेल सूखने लगे थे, पानी देना बंद कर रहे थे, वे इस विधि से खेती करने के बाद निर्बाध चल रहे हैं। रासायनिक गन्ना अधिक बढ़ने और अधिक वर्षा व हवाओं के चलने से गिर जाता है, जबकि पालेकर विधि से किया हुआ गन्ना जड़ों की अधिक पकड़ व गन्ने की मजबूती बढ़ने से अधिक बढ़वार के बाद भी नहीं गिरता है। सामान्यत: रासायनिक गन्ने में चीनी की मात्रा 9 से 10 प्रतिशत पाई जाती है। परंतु गाय आधारित पालेकर विधि से किए गए गन्ने में रिकवरी दर 12 प्रतिशत तक पाई गई है, जो स्वयं गन्ने से गुण या राब बनाने वालों तथा चीनी मिलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। वर्तमान समय में अधिक रासायनिक खादों व कोरोजन जैसे अधिकाधिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग लग रहा है। जिसके कारण गन्ने की कई प्रजातियों को रिजेक्ट किया जा चुका है। परंतु जब उसी गन्ने को पालेकर विधि से किया गया तो उसमें गन्ने का सड़न रोग नहीं लगा। उसके दो उदाहरण देना उपयुक्त रहेगा-पहला, सुगर मिल, बिसवां, जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के द्वारा 2017-18 में 24 किसानों को प्राकृतिक कृषि विधि से प्रयोग रूप में चुना गया। उनसे कहा गया कि आप अपने पूरे खेत में रासायनिक विधि से जैसे खेती करते हो करो, परन्तु उसी खेत में एक किनारे कुछ खेत कुछ लाइन गाय आधारित पालेकर विधि से करो। गन्ना तैयार होने पर आश्चर्यजनक परिणाम सामने आये। उसी खेत के रासायनिक गन्ने में लाल सड़न रोग लगा, परन्तु पालेकर विधि से किये गए गन्ने में लाल सड़न रोग नहीं लगा। अत: सुगर मिल ने उस गन्ने को बीज के लिए किसानों को दिया। दूसरा उदाहरण, गन्ना शोध संस्थान ने प्राकतिक खेती विधि के खेत व लैब में कई प्रकार के प्रयोग किए, परन्तु गन्ने में लाल सड़न रोग नहीं लगा। इसके विपरीत जिसमें पहले से रोग लगा था, उसमें कमी आई। बिसवां सुगर मिल का मानपुर में गन्ना फार्मज़ है, जिसमें 10-12 प्रजातियों के गन्ने रासायनिक विधि से एक ही खेत में अलग-अलग लाइनों में समान उर्वरक, कीट व रोगरोधकों का प्रयोग किया गया। परन्तु उस प्रयोग में केवल एक प्रजाति की दो लाइनों में गाय आधारित प्राकृतिक विधि का एक प्रयोग किया गया, जिसमें आच्छादन अलग से जोड़ दिया गया। अक्टूबर माह में गन्ने की बोवनी के बाद उड़द निकालने से बचे उड़द के अवशेष को उक्त गन्ने की लाइनों में बिछाकर आच्छादन कर दिया गया। आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला। इन लाइनों का गन्ना शेष गन्ने से मोटा और डेढ़ से दो फीट लंबा था। सुभाष पालेकर द्वारा विकसित प्राकृतिक कृषि विधि से गन्ना करने से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान और कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। **पराली का समाधान**- इस समय खरीफ की फसल धान, तिल्ली, उड़द, मूंग व ज्वार, बाजरा आदि कटने जा रहा है। पिछले कई वर्षों से धान की पराली जलाने से वायु प्रदूषण के मामले सामने आए हैं। जिसके कारण दिल्ली की वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गई। परिणामत: पराली जलाने पर रोक लगाई गई और अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया। प्राकृतिक विधि से गन्ना करने से पराली का पूरा उपयोग गन्ने में आच्छादन के लिए हो जाएगा और एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। **पानी की बचत**- आच्छादन से खेत का अधिकाधिक भाग ढका रहने से ह्यूमस बढ़ेगा और नमी अधिक दिन टिकेगी, जिससे पानी की बचत होगी। आच्छादन वायुमंडल से नमी लेकर भूमि को उपलब्ध कराएगा, जिससे पानी लगाने की अवधि बढ़ जाएगी। **वर्षाजल रिचार्जिंग में वृद्धि**- आच्छादन और जीवामृत के प्रयोग से खेत में केंचुए आ जाएंगे, जिससे खेत की प्राकृतिक जुताई और फसल के लिए सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति की निरन्तरता प्रारंभ हो जाएगी। केंचुओं द्वारा खेत में अनंत छिद्र कर दिए जाने से वर्षाजल की रिचार्जिंग बढ़ जाएगी।

-शिवराज सरकार को होगा करोड़ों रुपए का नुकसान

मध्य प्रदेश में पौने चार लाख टन धान की होगी नीलामी

प्रदेश सरकार छह लाख 45 हजार टन गेहूं की नीलामी करने के बाद अब धान की भी नीलामी होगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2019-20 की मिलिंग से शेष पौने चार लाख टन से अधिक धान को अब सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर दिया है। नीलामी से एक हजार 400 रुपए से लेकर आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल तक राशि मिलने की उम्मीद है। जबकि, जुलाई 2021 तक धान का प्रति क्विंटल औसत आर्थिक लागत दो हजार 476 रुपए है।

संवाददाता। भोपाल

सरकार को धान नीलाम करने के बाद भी करोड़ों की हानि होगी, पर सरकार के पास इसके अलावा अन्य विकल्प भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 25 लाख 54 हजार टन धान का उपार्जन किया था। इसमें से 20 लाख 47 हजार टन धान की मिलिंग हुई और चावल भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के लिए दिया गया। तीन लाख 82 हजार टन धान की मिलिंग अब तक नहीं हो पाई है। जबकि, राज्य के अनुरोध पर केंद्र ने बार-बार मिलिंग की अवधि में वृद्धि की। 29 अप्रैल 2021 को पत्र लिखकर केंद्र ने साफ कर दिया कि अब मिलिंग की अवधि में वृद्धि नहीं होगी और शेष धान का निराकरण राज्य ही करे।

धान गोदाम और कैंप में रखी

यह धान गोदाम और कैप में रखी हुई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक अप्रैल 2020 से मिलिंग प्रारंभ हुई। कोरोना काल में प्रतिमाह औसतन एक लाख टन धान की मिलिंग हुई थी। गति ठीक चल रही थी पर जुलाई अंत में चावल की गुणवत्ता को लेकर बालाघाट, मंडला सहित अन्य जिलों में कार्रवाई हुई और निम्न गुणवत्ता का चावल मिलर को लौटा दिया। इससे मिलिंग बंद हो गई। मिलर ने धान की गुणवत्ता का सवाल उठाया और टेस्ट मिलिंग करके धान लेने की मांग रखी पर केंद्र ने अनुमति नहीं दी।

कैबिनेट ने दी मंजूरी

मिलिंग नहीं होने से सरकार ने मिल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और मिलों को सील तक कर दिया पर यह कदम कारगर साबित नहीं हुआ। इसी तरह वर्ष 2017-18 की एक हजार 250 टन धान मिलिंग के लिए शेष है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने मिलिंग के लिए शेष धान को अब नीलाम करने का प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है।

गेहूं लेने को तैयार खरीदार

केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में छह लाख 45 हजार टन गेहूं लेने से इंकार करने के बाद सरकार ने इसे नीलाम करने के लिए छोटे-छोटे समूह बनाकर निविदा बुलाई तो परिणाम बेहतर सामने आए हैं। खरीदारों ने एक हजार 600 रुपए से लेकर दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर प्रस्तावित की है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने गेहूं की प्रति क्विंटल आधार दर एक हजार 590 रुपए तय की थी। निगम ने परीक्षण करने के बाद दर अनुमोदित करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति को भेज दिया है।

मूंग की भी होगी नीलामी

प्रदेश में चार लाख 39 हजार टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य सात हजार 196 रुपये प्रति क्विंटल पर किया है। जबकि, केंद्र सरकार ने दो लाख 47 हजार टन मूंग खरीदने की ही अनुमति दी थी। शेष मूंग को सेंट्रल पूल में लेने की मांग पिछले दिनों में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से की है।

औसत दर	संभावित विक्रय दर	संभावित हानि
2,476	800	640
2,476	1,000	564
2,476	1,200	487
2,476	1,400	411

नोट- दर प्रति क्विंटल और राशि करोड़ में।

कृषि विज्ञान केन्द्र ने रामपुर में खोला कृषक पुस्तकालय

अब किसानों को गांव में ही मिलेगी खेती की पूरी जानकारी

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को हर समय सरल और सुलभ ज्ञान प्राप्त होता रहे। इसके लिए कोलारस ब्लॉक के रामपुर गांव में संचालित कियोस्क सेंटर पर कृषक पुस्तकालय खोला गया है। जहां आकर गांव के किसान, किसान महिलाएं, पशुपालक, ग्रामीण युवक और युवतियां खेती-किसानी से जुड़ी पुस्तकें, कृषि पत्रिकाएं आदि कृषि साहित्य का लाभ उठा सकेंगे। जिससे किसानों को कृषि साहित्य से प्राप्त होने वाला ज्ञानार्जन खेती और पशुपालन आदि में काम आ सकेगा। देखने में आ रहा है कि इंटरनेट और वाट्सएप के प्रभाव के चलते आम लोगों में पढ़ने-लिखने में रुचि एवं प्रकाशित पुस्तकों से दूरी बनती जा रही है। आज कृषि, पशुपालन एवं कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर किसानों के खेती-बाड़ी में उपयोगी जानकारी से संबंधित ज्ञान से परिपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं व पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन किसानों और ग्रामीणों में इनको पढ़कर जानकारी हासिल करने की रुचि कम ही दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इन लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह के मार्गदर्शन में कोलारस ब्लॉक के रामपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र कृषक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया। कृषक पुस्तकालय के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमके भार्गव ने बताया कि केन्द्र द्वारा प्रकाशित कृषि साहित्य एवं बाहर से आने वाली खेती-किसानी से जुड़ी पत्रिकाएं आदि को पुस्तकालय के माध्यम से किसानों को पढ़ने और उनसे लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र के माध्यम से रामपुर कृषक पुस्तकालय में किसानों से जुड़े साहित्य को समय-समय पर उपलब्ध कराया जाता रहेगा। इस अवसर पर केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे। ग्रामीण कृषक पुस्तकालय की सफलता से कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा अन्य विकासखंडों में भी इस अभिनव पहल की शुरुआत भविष्य में की जाएगी। कृषि विज्ञान केन्द्र के समस्त वैज्ञानिक डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह, डॉ. जेसी गुप्ता, डॉ. एएल बसेड़िया, डॉ. नीरज कुशवाह, शोध सहायक विजय प्रताप सिंह भी इस पहल में अपने विषय से संबंधित समसामयिक जानकारी भी प्रसारित करेंगे।

किसानों को कृषि साहित्य और खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, पेम्पलेट्स आदि के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगे। इससे कृषि साहित्य से प्राप्त ज्ञानार्जन किसानों के काम आ सकेगा। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगारमूलक उद्यमों के लिए विस्तृत जानकारी भी प्राप्त होगी।

डॉ. एसपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं
प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी

हरियाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बनाएगी नया नियम

प्रदेश में किसान अपनी जमीन से भी पेड़ नहीं काट सकेंगे

विशेष संवाददात। भोपाल

हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा प्लांटेशन के लिए नया नियम बनाया जा रहा है। इस नियम के अंतर्गत अगर किसान अपनी निजी जमीन पर पेड़ लगाता है तो उसे काटने और उसका विक्रय करने के लिए वन विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पट्टाधारियों और लकड़ी का व्यापार करने वालों को नए नियम में कई सुविधाएं दी जाएंगी। मध्य प्रदेश पौधरोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 के अंतर्गत अगर किसान अपनी निजी भूमि पर पौधारोपण करता है तो उसे काटने के लिए वन विभाग की ट्रांजिट पास टीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान अगर चाहे तो गोदामों में बिना अनुमति के लकड़ी की टाल संग्रहित कर सकता है। उत्पादक अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात लकड़ी की टाल पर कास्ट प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित कर सकेगा। निजी भूमि के अलावा सरकार से पट्टा या हस्तांतरण से धारित की गई भूमि पर भी पौधे लगाने वालों को भी नियम में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

बेचने के लिए अनुमति जरूरी

अगर किसान अपनी निजी जमीन पर पौधे लगाता है और गोदाम या टाल वन संरक्षित क्षेत्र की परिधि में रहता है तो उसे बेचने के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। लकड़ी की ऐसी प्रजातियां, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अलावा लकड़ी के टाल या गोदाम से कोई भी इमारती लकड़ी या परवर्ती लकड़ी के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास की आवश्यकता नहीं होगी।

50 हजार का लगेगा जुर्माना

नए नियमों का अगर कोई किसान, व्यापारी या अन्य लोग उल्लंघन करता है तो उस पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा। इस मामले की अपील एसडीएम के यहां की जाएगी। वे अपने स्तर पर पूरे मामले की छानबीन कर आदेश जारी करेंगे।

नगरपालिका क्षेत्रों में नियम नहीं

नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगा। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इलाके नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, वह इस दायरे से बाहर हैं। वही अगर शहरी क्षेत्र की कालोनियां भी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अंतर्गत आती हैं तो वहां पर नियम लागू होगा। जल्द ही सभी जिलों के प्रमुख अधिकारियों को यह अध्यादेश लागू किया जाएगा।

चेतावनी के बाद भी कोल्ड स्टोरेज से 31 अगस्त तक नहीं हुई निकासी

लाल आलू निकाल रहा किसानों के आंसू

संवाददाता, भोपाल

आलू से चिप्स बनाने वाली लाल आलू की एलआर किस्म किसानों को रुलाकर उनकी आंखें लाल कर रही है। बाजार में आलू के भाव जमीन पर हैं। एलआर किस्म का कोई खरीदार नहीं है। दो लॉकडाऊन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि वे आगे क्या करें। आलू की खरीदारी नहीं होने से कोल्ड स्टोरेज में आलू भरे पड़े हुए हैं, जो किसानों की चिंता का कारण बन रहे हैं। कोरोना काल में आलू की कम खपत होना, आलू का निर्यात नहीं होना और आलू का अधिक उत्पादन किसानों की बड़ी समस्या बन गया है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि 31 अगस्त तक कोल्ड स्टोरेज में आलू की मियाद समाप्त होने के बाद अब कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने अखबारों में जाहिर सूचना देकर किसानों से आलू उठाने को कहा है। अन्यथा वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

कोल्ड स्टोरज फुल- प्रदेश में आलू के कुल उत्पादन का 45 से 50 प्रतिशत स्टॉक कोल्ड स्टोरेज में जमा है। प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में आलू के करीब 70 लाख कट्टे जमा हैं। इनमें से 25 लाख कट्टे तो अकेले इंदौर जिले के 100 कोल्ड स्टोरेज में चिप्स बनाने वाली किस्म लाल आलू के ही हैं। 70 लाख कट्टे और 60 किलो के हिसाब से 42 लाख मीट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोरेज में जमा है, जो मध्यप्रदेश के वार्षिक औसत उत्पादन 33 लाख मीट्रिक टन से कहीं अधिक है।

भावांतर की उम्मीद- किसान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आस लगाए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह प्याज में भावांतर योजना लागू की थी, उसी तरह से आलू में भी भावांतर से किसानों को बेहद मदद मिलेगी जिससे वे घाटे में नहीं रहेंगे। विगत दो वर्षों से मध्यप्रदेश के चिप्स निर्माता मप्र के बजाए गुजरात का आलू अधिक खरीद रहे हैं क्योंकि वह गुणवत्ता में अधिक अच्छा है। इसलिए भी कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी नहीं हो पाई।

आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	उत्पादन टन में	उत्पादकता टन प्रति हेक्टेयर
2017-18	136290.21	3144642.92	23.07
2018-19	145736.50	3309667.31	22.71
2019-20	149435.36	3408606.84	22.81
2020-21	153432.31	3511401.01	22.89

2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमानुसार

उत्पादन में मप्र 5वें नबर पर

मध्यप्रदेश में आलू की खेती मुख्य रूप से इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर जिलों में की जाती है। इसके अलावा अन्य 16 जिलों में आलू की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश में 5वें स्थान पर आता है।

पूरे भारत में आलू का कोई खरीदार नहीं हैं। किसी भी किस्म का अच्छी गुणवत्ता वाला आलू 3 से 5 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दो रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है। किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। मेरा गांव उज्जैन से 12 किमी दूर मक्सी रोड पर है। मेरे अकेले के गांव में आलू उत्पादक किसानों को 4 करोड़ रुपये का घाटा हो गया है।

रामेश्वर पाटीदार, पूर्व मंडी अध्यक्ष, उज्जैन

-भारतीय कपास निगम ने देश के साढ़े पांच हजार किसानों को निःशुल्क दी मशीन

मप्र के किसानों को मुफ्त में मिली कपास प्लकर मशीन

भोपाल/नई दिल्ली

भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत सभी कपास उत्पादक राज्यों (आकांक्षी जिलों सहित) में 5,543 सीमांत और छोटे किसानों के बीच करीब चार करोड़ रुपए की कीमत की कपास प्लकर मशीने वितरित की है। कपास प्लकर मशीनें कपास उत्पादक सभी राज्यों के किसानों को दी गई हैं। यह मशीन अलग-अलग कपास उत्पादक राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को 100, हरियाणा को 135, राजस्थान को 120, गुजरात को 600, महाराष्ट्र को 839, मप्र को 626 , तेलंगाना को 547, कर्नाटक को 1228, उड़ीसा को 700 राज्य में कपास प्लकर मशीनें दी गई हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र- मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन और जवार कपास उत्पादक जिले हैं। भारत में हाथों के द्वारा अधिकांश कपास पौधों से अलग किया जाता है, जिसके लिए ज्यादा श्रमबल की जरूरत पड़ती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि जैसे दुसरे प्रमुख कपास उत्पादक देशों के विपरीत, भारत में कपास किसानों की छोटी भूमि जोत, बोवनी/कपास को पौधे से निकलने के पैटर्न और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण बड़ी मशीनों द्वारा पूरी तरह से मशीनीकृत कटाई भारत में सफल नहीं हुई है। किसानों के लिए लागत को कम करने के लिए हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन एक विकल्प है और मानव श्रम के साथ कपास को पौधे से अलग करने के कारण खेतों के स्तर पर संदूषण को रोकने का एक हल है।

कपास प्लकर मशीन आठ हजार में

भारत में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत काम की मशीन हैं। हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन एक हल्के वजन (लगभग 600 ग्राम) की है, जिसके अंदर रोलर्स की एक जोड़ी होती है, जिसके बाहरी परिधि पर छोटे किनारों वाले दांत होते हैं और यह हल्के वजन 12 वोल्ट द्वारा संचालित होता है। कपास रोलर्स में उलझ जाता है और सीधे उससे जुड़े कलेक्शन बैग में इकट्ठा हो जाता है। मशीन का डिजाइन उसे क्षेत्र में काम करने के लिहाज से आसान बनाता है और यह 8,000 रुपए प्रति मशीनों की कम कीमत के साथ किफायती भी है।

कपास प्लकर मशीन से लाभ

कपास किसानों के लिए मैनुअल पिकिंग में स्वास्थ खतरों के जोखिम को कम करना। कपास की कटाई के कौशल में सुधार, दुर्लभ और महंगे श्रम पर निर्भरता कम करना तथा कपास किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। खेतों के स्तर पर संदूषण को कम करके कपास की गुणवत्ता में सुधार करना। कटाई की लागत में कमी, कम कचरा एवं संदूषण और बेहतर गुणवत्ता वाले कपास की बिक्री पर प्रीमियम के साथ कपास किसानों का वित्तीय लाभ बढ़ सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले स्वदेशी कपास की उपलब्धता के कारण सूती धागे, वस्त्र और मूल्य वर्धित उत्पादनों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सकती है।

फैटयुक्त दूध के भाव में 20 रुपए किलो की वृद्धि

उज्जैन दुग्ध संघ ने दूध खरीदी के भाव में किया इजाफा

वंदना परमार, उज्जैन

सहकारी समिति के द्वारा जो दूध खरीदा जाता है उसमें पशुपालकों को दूध की कीमत उसमें मौजूद फैट की मात्रा से तय होती है। ऐसे में मप्र के उज्जैन दुग्ध संघ ने सहकारी समिति के माध्यम से क्रय किए जा रहे दूध के भाव में 20 रुपए प्रति किलो फैट की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि का सीधा लाभ सहकारी समिति से जुड़े किसानों और पशुपालकों को होगा। सहकारी समिति को हो रहे लगातार लाभ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 40वें वार्षिक अधिवेशन में उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासन एवं संभागीय आयुक्त संदीप यादव ने कहा कि सहकारी समिति के माध्यम से क्रय किए जा रहे दूध के भाव में 20 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति किलो फैट की वृद्धि की गई है।

यादव ने कहा कि विगत वर्ष 2020-21 में 1,241 सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति-दिन औसतन 1.52 लाख लीटर दूध संकलित किया गया। दुग्ध संघ द्वारा अच्छी मात्रा में दूध संकलित करने के साथ वितरण व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल से अगस्त 2021 तक मात्र पांच माह में लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए लाभ अर्जित किया गया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक संघ अच्छा वित्तीय लाभ अर्जित कर लेगा। संघ की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होने से पहली बार दुग्ध उत्पादकों को लाभांश का वितरण किया जा सकेगा।

दुग्ध समितियों की बढ़ी आय

दुग्ध समितियों द्वारा 6979 मीट्रिक टन पशु आहार, 15 मीट्रिक टन मिनरल मिक्चर और 15 मीट्रिक टन चारा बीज का विक्रय किया गया। संघ के प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा 112 सदस्यों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया। दुग्ध समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष में 3.94 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया।

कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में संघ द्वारा औसतन 46 हजार लीटर पैक्ड दूध का प्रतिदिन स्थानीय बाजार में विक्रय किया गया। संघ द्वारा 1475 मीट्रिक टन घी, 1279 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण एवं 1805 में टन मिल्क पाउडर का मुख्य रूप से विक्रय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 6.8 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया।

संदीप यादव, आयुक्त, दुग्ध संघ उज्जैन संभागीय

मल्टीलेयर फार्मिंगः एक एकड़ में गोभी धनिया समेत तीन फसलों से बढ़ गई आमदनी

धार के सीताराम सिर्फ तीन फसलों से सालाना कमा रहे आठ लाख

धार। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 फीसदी के आसपास है। कम जमीन होने के कारण खेती के सहारे ऐसे किसानों के सामने अपने परिवार को गुजारा करना आसान नहीं होता है। ऐसे किसानों के लिए मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल बेहद कारगर हो सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के आवलिया गांव के किसान सीताराम निगवाल पिछले छह सालों से सब्जियों की मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं और सालाना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नए तरीके से खेती के लिए उन्हें आईसीएआर की तरफ से एक लाख का नगद इनाम भी मिल चुका है। सीताराम के पास परिवार में बंटवारे के बाद उनके हिस्से में दो एकड़ जमीन आई थी। जिसमें वे सोयाबीन, ज्वार, मक्का, गेहूं और चना की परंपरागत खेती करते थे। कम उत्पादन और अधिक लागत के कारण परिवार का गुजारा भी कठिन था। परंपरागत खेती में अधिक श्रम, खर्च और समय लगता, लेकिन अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता था। कई सीजन तो फसल की लागत भी नहीं मिल पाती थी। थक हारकर उन्होंने कुछ नया करने की ठानी और सहफसली बहुफसली यानि एक साथ कई सब्जियों की खेती शुरू की। सीताराम बताते हैं कि जमीन कम थी और खेती जो कर रहे थे उससे परिवार नहीं चल रहा था। छह साल पहले हमने धार स्थित कृषि विज्ञान केंन्द्र से संपर्क किया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने कम जमीन को देखते हुए सब्जियों की मल्टीलेयर फार्मिंग की सलाह दी। कुछ सालों तक मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से खेती करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इस मॉडल से सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर रहा हूं।

सही समय और उपयुक्त किस्म की बोवनी किसानों की लाएगी अच्छे दिन

अक्टूबर में सब्जियों की खेती बना देगी आत्मनिर्भर

भोपाल। पारंपरिक खेती के बजाए अब किसानों का रुझान अधिक लाभ देने वाली फसलों के प्रति बढ़ रहा है। ऐसे में सब्जियों की खेती सबसे पहले आती है, जिनसे किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अक्टूबर माह में कई सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही सही समय पर सब्जी के खेती से किसान आत्मनिर्भर भी होंगे। अक्टूबर में ब्रोकली, फूलगोभी, आलू, टमाटर, मटर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, धनिया, आलू, सौंफ के बीज, गाजर, शलगम आदि की खेती की जा सकती है। इस समय इन सब्जियों की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलने के साथ ही बेहतर मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। हम यहां इसमें से उन प्रमुख फसलों के बारें में जानकारी देंगे जो आपकी कमाई बढ़ा सकें।

1. ब्रोकली की खेती : ब्रोकली गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत एक प्रमुख सब्जी है। यह एक पौष्टिक इटालियन गोभी है। जिसे मूलत: सलाद, सूप, व सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रोकली दो तरह की होती है। स्प्राउटिंग ब्रोकली और हेडिंग ब्रोकली। इसमें से स्प्राउटिंग ब्रोकली का प्रचलन अधिक है। हेडिंग ब्रोकली बिलकुल फूलगोभी की तरह होती है। इसका रंग हरा, पीला अथवा बैंगनी होता है। हरे रंग की किस्म ज्यादा लोकप्रिय है। सितंबर मध्य से नवंबर के शुरू तक ब्रोकली की पौध तैयारी की जा सकती है। बीज बोने के लगभग 4 से 5 सप्ताह में इसकी पौध खेत में इसकी रोपाई की जा सकती हैं।

ब्रोकली की उन्नत किस्में: के.टी.एस.-1 : इस किस्म के शीर्ष हरे रंग के कोमल डंठल युक्त होते हैं, जिनका औसत वजन 200-300 ग्राम होता है और रोपाई के लगभग 80-90 दिनों बाद काटने योग्य हो जाता है। मुख्य शीर्ष काटने के कुछ दिनों बाद छोटे-छोटे शीर्ष शाखाओं की तरह मुख्य भाग के रूप में पत्तियों के कक्षों से निकलते हैं।

पालक समृद्धि :

यह किस्म भी हरे शीर्ष वाली स्प्राउटिंग ब्रोकोली किस्म है। जिसका शीर्ष भाग बड़ा एवं लम्बे कोमल डंठल युक्त होता है। प्रत्येक शीर्ष का औसत वजन 25-300 ग्राम होता है। मुख्य शीर्ष को काटने के बाद छोटे-छोटे शीर्ष पत्तों के कक्षों से निकलते हैं। यह किस्म 85-90 दिनों में रोपाई के बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसमें येलो आई रोग एवं ब्रैक्टिंग विकार के लिए प्रतिरोधिता पाई जाती है। एनएस- 50- यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली संकर किस्म है। इनके हेड गठीले, समरूप एवं गुम्बदाकार होते हैं। यह किस्म कैट आई से रहित है। इसके पौधे मृदुरोमिल आसिता एवं काला सडन रोग के प्रति सहनशील है। इसका बीज नामधारी मार्क से बाजार में मिलता है।

2. फूलगोभी की खेती

यह समय मध्यकालीन फूलगोभी की उन्नत प्रजातियां जैसे- इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा दिवाली, पूसा कातकी, पंता सुभरा की रोपाई का उचित समय है। इसके लिए खेत की आखिरी जुताई पर 120 किग्रा नाइट्रोजन, 100 किग्रा. फास्फोरस, 60 किग्रा पोटाश एवं 10 किग्रा बोरेक्स प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इससे अच्छा उत्पादन मिलता है। 50 किग्रा यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए।

3. पालक की खेती

पालक की खेती के लिए आल्ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पालक नं. 51-16, वर्जीनिया सेवोय, अर्ली स्मूथ लीफआदि उन्नत किस्मों की रोपाई की जा सकती है। पालक का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 25 से 30 किग्रा प्रति हेक्टर बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। पालक की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए खाद व उर्वरक की संतुलित मात्रा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। भूमि में खाद व उर्वरक की मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले खेत की मृदा का परीक्षण करवा लेना चाहिए।

मेथी की खेती

मेथी एक औषधीय गुणों से भरपूर फसल है। इसके सूखे दाने का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। वहीं आयुर्वेद की दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेथी की खेती के लिए उन्नत किस्में जैसे-पूसा अर्ली बन्चिंग, मेथी कसूरी व हिसार सोनाली किस्में 6-7 कटाई देती हैं। मेथी की खेती के लिए जीवांशयुक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट चिकनी मिट्टी सर्वोतम होती है। खेत तैयार करते समय 17 टन प्रति हेक्टर गोबर की अच्छी सड़ी हुई देशी खाद के साथ 2.7 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा आधा बोरा यूरिया डालें। पालक, मेथी, कसूरी मेथी के लिये पंक्ति से पंक्ति एवं पौधें से पौधें की दूरी पर बोवनी करनी चाहिए।

मूली की खेती

इस माह मूली की एशियाई किस्मों जैसें-जापानी, व्हाइट, पूसा चेतकी, हिसार मूली-1, कल्याणपुर-की बोवनी करना फायदेमंद है। मूली का एक हेक्टर में बोवनी के लिए 6-8 किग्रा बीज की जरूरत होती है। अगेती मूली की एशियाई किस्मों जैसे-पूसा देशी, पालक ह्रदय, जापानी, व्हाइट, पूसा चेतकी, की बोवनी कर सकते हैं। मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन किस्मों का 8-10 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है।

टमाटर की खेती और उन्नत किस्में

टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए इसकी उन्नत और संकर प्रजातियों के बीच की बोवनी नर्सरी में करें। अगेती किस्मों जैसे-गोल्डन, पूसा हाइब्रिड-2, पूसा सदाबाहर, पूसा रोहिणी , पूसा-120, पूसा गौरव, काशी अभिमान, काशी अमृत, काशी विशेष, पीएच-8, पीएच-4 की बुआई 15 सितंबर तक व पछेती किस्मों/संकर किस्मों की बोवनी 15 सितंबर के बाद प्रारंभ करें। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए करने के लिए संकर और उन्नत प्रजातियों के लिए 250-300 ग्राम और 500-600 ग्राम प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त होता है।

7. धनिया की खेती

धनिया की उन्नत प्रजाति पंत धनिया-1, पंत हरितिमा, आजाद धनिया-1, मोरक्कन, गुजरात धनिया-1, गुजरात धनिया-2, जवाहर धनिया-1, सीएस-6, आरसीआर-4, सिंधु की बुआई सितंबर में वर्षा सप्ताह होने पर कर सकते हैं। इसके लिए 15-20 किग्रा बीज प्रति हैक्टर के लिए पर्याप्त होता है।

आलू की अगेतीकी खेती

आलू की अगेती फसल के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। अगेती आलू की बुआई के लिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी कुबेर, कुफरी बहार, कुफरी सूर्या, कुफरी अशोका आदि किस्में मुख्य हैं। आलू की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मृदा, जिसमें जैविक पदार्थ की बहुलता हो, उपयुक्त है। खेती की तैयारी करते समय खेत की आखिरी जुताई पर 100 किग्रा नाइट्रोजन, 80 किग्रा फास्फोरस एवं 80 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टर की दर से बोवनी के समय प्रयोग करना चाहिए।

मटर की अगेती प्रजातियां

मटर की अगेती प्रजातियों की बोवनी सितंबर से अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक की जा सकती है। मटर की अगेती प्रजातियों में जैसे-आजाद मटर-3, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और अगेती प्रमुख हैं। मटर की इन प्रजातियों की सबसे खास बात यह है कि यह 50 से लेकर 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं, जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है और किसान दूसरी फसलों की बोवनी भी कर सकते हैं। बोवनी के लिए प्रति हेक्टर 80 से लेकर 100 किग्रा बीज की जरुरत पड़ती है।

सरसों की उन्नत किस्में कर देंगी मालामाल

भोपाल।

इस वर्ष न केवल खुले बाजार में तिलहन के अधिक भाव हैं, बल्कि सरकार ने भी सरसों जैसी तिलहन फसल के न्यूनतम समर्थन में काफी वृद्धि की है। जिससे किसानों का रुझान तिलहन फसलों की ओर बढ़ा है। ऐसे में किसानों को अधिक लाभ के लिए अधिक उत्पादन देने वाली सरसों की किस्मों का चयन करना बहुत जरुरी है। यदि किसान उन्नत किस्मों के साथ्ज्ञ खेती करें तो सरसों की फसल उन्हें मालामाल कर सकती है। समय पर सरसों कि बुवाई से फसल को रोग और कीटों से बचाया जा सकता है। बारानी क्षेत्र में सरसों कि बोवनी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच की जा सकती है। वहीं सिंचित क्षेत्र में सरसों कि बोवनी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक करना चाहिए। देर से बुवाई की जाने वाली किस्मों की बुवाई 10 नवंबर तक की जा सकती है।

बीज कि मात्रा- अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बीज कि मात्रा भी अलग होता है। बीज की दर सिंचित तथा बारानी क्षेत्रों पर निभज़र करता है। सिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों का बीज 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कि दर से बीज का उपयोग करना चाहिए। बारानी क्षेत्रों के लिए बीज का दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुवाई किसान कर सकते हैं।

सरसों कि उन्नत किस्में

आरएच-30 : सरसों कि यह किस्म सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी उत्पादन क्षमता 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल कि मात्रा 39 प्रतिशत तक होती है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

पूसा बोल्ड : सरसों की पूसा बोल्ड किस्म राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं। इसकी फलियां मोटी और इसके एक हजार दानों का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। इस प्रजाति का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल कि मात्रा सबसे अधिक 42 प्रतिशत होती है। यह किस्म 130 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

आरजीएन-73 : सरसों कि यह प्रजाति सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। यह किस्म कई खूबियों के लिए जानी जाती है। इस किस्म कि सरसों कि फलियां पकने पर चटकती नहीं हैं।

सरसों की संकर किस्में

एनआरसीएचबी-506 : सरसों कि यह किस्म समय पर बोवनी और सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 16 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तेल कि मात्रा 41 प्रतिशत रहती है। यह किस्म 130 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

डीएमएच-1 : सरसों कि यह किस्म रोग तथा कीटों के प्रति सहनशील है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 17 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तेल कि मात्रा 39 प्रतिशत तक रहती है। यह 145 से 150 दिनों में तैयार होने वाला किस्म है।

पीएसी-432 : सरसों कि यह किस्म उत्तर भारत, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त है। इस किस्म कि सरसों से 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कि दर से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सरसों की संकर किस्म में तेल कि मात्रा 41 प्रतिशत रहती है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

विनोद शाह के नवाचार ने घटाई खेती की लागत

विदिशा। खेती को आसान और लाभकारी बनाने के लिए नित नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, जिनसे किसानों काफी लाभ भी हो रहा है। ऐसा ही एक प्रयोग विदिश जिले के ग्राम चक्क पाटनी के किसान विनोद शाह ने किया।

विनोद शह नेबारिश का पानी रोककर धान की पौध रोप दी और गेहूं की फसल के अवशेष से तैयार जैविक खाद का उपयोग कर सोयाबीन की फसल को कीट प्रकोप से बचा लिया। विनोद के इस प्रयोग से उनके खेत में धान और सोयाबीन दोनों फसल लहलहा रही हैं।

खरीफ सीजन में इस बार किसान कहीं अतिवृष्टि से तो कहीं कीट प्रकोप से फसल बर्बाद होने के कारण परेशान हैं लेकिन विनोद शाह इन परेशानियों से मुक्त हैं। वह कहते हैं कि खेत में तालाब बनाने से आसपास के खेतों में जलभराव नहीं हुआ। वहीं, जैविक खाद के उपयोग से सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक जैसी बीमारियां निस्प्रभावी रहीं। जिसकी वजह से उनके खेत की फसल अन्य किसानों की फसल से बेहतर है। बताते हैं कि सोयाबीन के पौधे साढ़े तीन फीट ऊंचे हो गए हैं। फलियों में दाने का भराव भी अच्छा है। जिसका फायदा अधिक पैदावार के रूप में होगा।

खेत में तालाब बनाया और की धान की सिंचाई

विनोद शाह के खेत में पानी का स्रोत नहीं था। उन्होंने जून माह में ही बारिश का पानी जमा करने के लिए एक तालाब बना लिया। दो दिन की बारिश में यह तालाब लबालब हो जाता है। शाह ने 60 गुणा 60 फीट के एक खेत में करीब पांच फीट गहरी खोदाई कराई। बारिश का पानी तालाब में इकठठा हो गया। इसी से वह धान की फसल के साथ अन्य फसल की सिंचाई भी पंप लगाकर करते रहे। जब-जब बारिश होती, उनका यह तालाब फिर लबालब हो जाता। इस तरह उनकी सिंचाई की जरूरत पूरी होती रहती। शाह ने पहली बार 12 बीघा में धान की फसल लगाई है। जिसकी पूरी सिंचाई तालाब के पानी से ही हुई है। शाह ने धान और सोयाबीन की फसल में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया।

शिवपुरी: सिंगल क्लिक से शिवराज ने दी 435 करोड़ रुपए की सौगात

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बनाया कारखाने का मालिक

संवाददाता। शिवपुरी

शिवपुरी में जन कल्याण और सुराज अभियान कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं को कारखाने का मालिक बना गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेक होम राशन संयंत्र की चाबी सौंपते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में पोषण आहार बनाने का कारखाना अब कोई ठेकेदार नहीं, बल्कि स्व-सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी। उससे होने वाला लाभ भी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के खाते में जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार हरसंभव कार्य करेगी।

स्व-सहायता समूह की महिलायें ही स्कूल के बच्चों के गणवेश सिलने का कार्य करेंगीं, राशन की दुकानें भी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से संचालित की जाएंगी। साथ ही उपार्जन का कार्य भी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर सिंगल क्लिक के जरिये प्रदेश की 20 हजार महिला स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत ढाई सौ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की। साथ ही सिंगल क्लिक के जरिए ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की दो लाख 27 हजार 687 महिलाओं को 22 करोड़ 77 लाख रुपए का आहार भत्ता और बाढ़ पीड़ितों को 163 करोड़ 28 लाख रुपए राहत राशि के रूप में वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर शिवपुरी जिले के 80 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी सिंगल क्लिक से किया। इसकी लागत 305 करोड़ रुपए है। इस दौरान प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा एवं गुना-शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद केपी यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वसहायता समूह से जुड़ी 10 हजार से अधिक महिलाएं मौजूद थीं।

आहार तो मां ही दे सकती है, कोई ठेकेदार नहीं

शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसी को आहार तो मां, बहन या बेटी ही दे सकती है, कोई ठेकेदार नहीं है। इसलिए प्रदेश के सभी सात कारखाने महिलाएं ही चलाएंगी और इसका लाभ भी उन्हें ही मिलेगा। इस दौरान शिवराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कहा कि कोई चिंता न करे। यदि कोई शेष रह भी गया तो अभी सर्वे चल रहा है। हमारा खजाना गरीबों के लिए खाली नहीं है।

सिंधिया बोले- डबल इंजन सरकार है तो विकास ही होगा

वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार है, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक हमारी सत्ता है, इसलिए विकास तो होगा ही। मध्यप्रदेश में महिलाओं का यह काम पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट में पोषण के संबंध में बड़ा फैसला लिया है।

-मंत्री बोले-दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं किसानों के साथ हूं

कोल्ड स्टोरेज में आठ करोड़ रुपए का आलू हुआ अंकुरित

» **प्रबंधन ने कहा**- मौसम के प्रभाव से किसानों का आलू खराब
» **किसानों ने कहा** : प्रबंधन की लापरवाही से खराब हुआ आलू
» 40 गांवों के 1 हजार किसानों ने 55 हजार क्विंटल रखे थे आलू

संवाददाता। इंदौर

कोरोना काल में आर्थिक मंदी से हर क्षेत्र उबरने की कोशिश में है, लेकिन इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के एक हजार से ज्यादा किसानों को बड़ा नुकसान हो गया। उनके कोल्ड स्टोरेज में रखे 8 करोड़ रुपए कीमत के 55 हजार क्विंटल आलू खराब हो गए। किसानों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन की लापरवाही से आलू खराब हुए हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज मैनेजर का कहना है कि मौसम के प्रभाव से आलू खराब हुए हैं। इसके जिम्मेदार किसान ही हैं।

वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह सरकार किसानों की है। मैं हर समय किसानों के साथ हूं। हर संभव उनका साथ दिया जाएगा। दरअसल, मामला विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन बडोदा, बूड़ी बरलई, बरलगई जागीर, हनुतिया, मंडला, उदा, लसूड़िया परमार, कदवाली खुर्द, कदवाली बुजुर्ग, कदनाल बुजुर्ग, सिलोटिया, पलासिया सहित आसपास के 40 से ज्यादा गांवों के किसानों का है। किसान नेता व पूर्व जनपद सदस्य हंसराज मंडलोई व पूर्व जिला पंचायत सदस्य हुकुमचंद मालवीय बताया कि जिले के 40 गांवों के 1 हजार से ज्यादा किसानों ने अर्जुन बड़ोदा गांव में बने झंवर कोल्ड स्टोरेज में फरवरी में 55 हजार क्विंटल आलू रखे थे। ये आलू 3 श्रेणियों चिप्स, राशन और बीज के रूप में थे। इसके बाद अगस्त में जब किसान आलू लेने गए, तो कुछ दिन बाद लेने को आने का कहा गया।

दवाई छिड़काव पर टालमटोल

इस बीच करीब एक माह से किसानों ने कई चक्कर लगाए। बताया गया कि मौसम के प्रभाव के कारण दवाई का छिड़काव किया है, इसलिए कुछ दिनों बाद दिए जाएंगे। एक माह से ज्यादा गुजर जाने के बाद टालमटोल की गई। पता चला कि अधिकांश आलू खराब होकर अंकुरित हो गए हैं, जो किसी काम के नहीं है।

बाहर फेंकने पर फैलेगी बीमारी

खास बात है कि 55 हजार क्विंटल आलू अगर बाहर फेंके जाते हैं, तो बीमारी फैलेगी। कोल्ड स्टोरज में अब काफी दुर्गंध है। उसे नष्ट करने के प्रयास नहीं किए गए हैं। किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन किसानों से एक सीजन के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल किराया वसूलता है। स्टोरेज संचालक अनिल झंवर ने बिजली बचाने के लिए 15 अगस्त को ही चिप्स के आलू वाला चेम्बर बंद कर दिया, जिससे 45 हजार क्विंटल आलू खराब हो गए। ऐसे ही जो आलू बीज के लिए रखे थे, वे सारे अंकुरित हो गए। अब ये बाजार में बेचने योग्य ही नहीं बचे हैं।

मिट्टी लगे आलू कट्टों में पैक थे

उधर, झंवर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर अशोक पटेल का कहना है कि मौसमी प्रभाव से आलू खराब हुए हैं। आलू का फरवरी से जुलाई तक कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, लेकिन कई किसान 110 दिन की बजाय 90 दिन में ही जमीन से आलू निकाल लेते हैं व आलू की साफ सफाई करने में लापरवाही बरतते हैं। वे आलू में मिट्टी लगी होने के बावजूद कट्टे में पैक कर देते हैं। आलू जुलाई माह में ही निकाल लेना चाहिए, लेकिन किसान बाजार में भाव बढ़ने के इंतजार में देरी करते हैं। इससे आलू खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।

कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू अंकुरित होना गंभीर है। इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री खुद किसान के बेटे हैं व यह सरकार किसानों की है। मैं हर समय किसानों के साथ हूं। उनका ध्यान रखा जाएगा।
तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक

सीएम ने की पीएम मुलाकात, मोदी ने दिया सुझाव

मप्र में कराएं चंदन की खेती

» किसानों के लिए यह बेहतर विकल्प
» मप्र सरकार जल्दी वर्कआउट करेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक के बाद शिवराज ने कहा कि विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मप्र में चंदन की खेती का सुझाव दिया। इसके अलावा इथेनॉल पॉलिसी पर भी विचार-विमर्श हुआ। शिवराज के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रॉप पैटर्न बदलाना चाहिए। इसको लेकर शिवराज ने कहा कि यह किसानों के लिए प्रधानमंत्री का सुझाव बेहतर विकल्प है। चंदन के अलावा बांस की पैदावार के लिए अमरकंटक व अन्य स्थानों को चिन्हित किए जाएंगे। मप्र सरकार इसको वर्कआउट करेगी। प्रधानमंत्री से इथेनॉल को लेकर भी बात हुई है। मप्र में इथेनॉल बनाने वाली कई कंपनियां आई हैं। अब तक 28 कंपनियों ने प्लांट लगाने का आवेदन किया है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)